

## तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र

तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। इसके विषयक्षेत्र को लेकर प्रमुख समस्या यह है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या-क्या सम्मिलित किया जाए और क्या-क्या अध्ययन से बाहर रखा जाए। जी. के. रावर्स ने अपनी पुस्तक 'वाट इज कम्पैरेटिव पोलिटिक्स?' में लिखा है कि 'तुलनात्मक राजनीति में अधिक आधाभूत समस्या इसकी उचित और तर्कसंगत सीमाओं की हैं।'

तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को लेकर पारम्परवादियों एवं आधुनिक राजनीतिशास्त्रियों में गहरा मतभेद है। संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित सूक्ष्म संरचना का तथा संविधान द्वारा नियंत्रित किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाना चाहिए। आर्से ने 158 संविधानों की तुलना कर उन्हें कई वर्गों में बांटा और आदर्श राज्य को खोजने का प्रयत्न किया। वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और सूक्ष्म राजनीतिक

प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक अनुभव-संस्थाओं, व्यवहारों को सजाती प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करना आज की तुलनात्मक राजनीति का विषय बन गया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था या औपचारिक संस्थाओं को ही राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में तुलना करनी चाहिए।

तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत व्यवस्था में इसके विषय क्षेत्र के संबंध में मुख्य मान्यता कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन की रही है। इसे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का कानूनी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा नियंत्रित किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाता चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह न केवल शासन संस्थाओं का अध्ययन है बल्कि इनमें शासन व्यवहार के प्रतिमान तथा और राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन सम्मिलित है।

Dr. Humma Aiza  
Asst. professor